जिसको रोटी
न मिलने से
मरना है उसे तो ईश्वर
रोटी में ही देखने में
आवेगा।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोकजीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 209 | जयपुर. शनिवार . | 28 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

केजरीवाल के 'शीश महल' का मीडिया ने किया दीदार, 58.83 करोड़ के खर्च का हिसाब सार्वजनिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को मीडिया के दौरे के लिए खोला। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस आवास को शीश महल का नाम दिया है। सरकार की योजना आने वाले दिनों में एक टिकटिंग सिस्टम के जरिए इस बंगले को आम जनता के लिए खोलने की है। मीडिया के दौरे के दौरान, अधिकारियों ने वहां मौजूद महंगा फर्नीचर दिखाया। इसमें 11.56 लाख रूपये का झूमर, 5.47 लाख रूपये का सोफा, 5.58 लाख रूपये की कुर्सियां, 6.79 लाख रूपये की सेंट्रल टेबल और 5.69 लाख रूपये के पर्दे शामिल थे। इस बंगले के नवीनीकरण और फर्नीचर पर कुल 58.83 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है, चूंकि यहां जनता का पैसा लगा है, इसलिए हमें जनता को पाई-पाई का हिसाब देना होगा। हमें यह बताना होगा कि उनका पैसा आखिर कहां खर्च हुआ है, असल में, हर सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस सुविधा को दिल्ली की जनता के लिए खोला गया है। आज हमने मीडिया को आमंत्रित किया है, बहुत जल्द, दिल्ली की जनता भी यहां आकर इसे खुद देख सकेगी। हमने इस परियोजना के लिए खरीदी गई वस्तुओं का पूरा विवरण सार्वजनिक कर दिया है। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, आज से दिल्ली और पूरे देश की जनता इस 'शीश महल' को देख सकेगी। आज इसे मीडिया के लिए खोल दिया गया है। आपके कैमरों के जरिये, पूरा देश उस भ्रष्टाचार और लूट के घिनौने खेल को देख पाएगा जिसे केजरीवाल ने तब खेला, जब दिल्ली कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी। जिस व्यक्ति ने कभी दावा किया था कि वह एक कमरे के घर में रहेगा, उसने जनता के पैसे का इस्तेमाल करके भारी भ्रष्टाचार किया है। यहां इस्तेमाल की गई चीजें दुनिया के अलग-अलग देशों से मंगाई गई हैं, मार्बल वियतनाम से आया है, क्रॉकरी किसी और देश से आई है और मेजें किसी अन्य देश से मंगाई गई हैं। आज, आपके कैमरों के जरिये, पूरा देश अपनी आंखों से इस सच्चाई को देख सकेगा।

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला खारिज

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी की नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना। इसके साथ ही विधायक अखरूज्जमान की मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्ति भी रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 10 दिन के भीतर नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी गई थी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले पर दोबारा विचार करने और नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि नया फैसला कारणों के साथ होना चाहिए। इसके लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है। अदालत ने अखरूज्जमान को मुख्य सचेतक नियुक्त करने के फैसले को भी रद्द कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। यह मामला तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। शोभनदेब चट्टोपाध्याय का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए नामित किया था। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को दरकिनार करते हुए ऋतब्रत बनर्जी को इस पद पर मान्यता दे दी। ऋतब्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए विधायकों के एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस गुट ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा पेश किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3 जून को अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी थी। उन्होंने अलग हुए गुट की ओर से पेश किए गए दावे को स्वीकार किया था। इसके खिलाफ सोवंदेब चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रूख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी की ओर से किए गए नामांकन की अनदेखी की। इस मामले की सुनवाई पहले एकल पीठ और फिर खंडपीठ में हुई। अगस्त में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को अंतरिम तौर पर जारी रखने की अनुमति दी थी। यह व्यवस्था दो महीने के लिए थी। साथ ही, एकल पीठ को नियुक्ति के खिलाफ मुख्य याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था। एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 21 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार को नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया गया।

लोकसभा की सीटों में 50% तक इजाफे की तैयारी, 2051 तक परिसीमन पर रोक का प्रस्ताव

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी



नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस फैसले के साथ ही परिसीमन को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके तहत मौजूदा सीटों की संख्या में 50 फीसदी तक इजाफा करने की योजना है। सरकार के प्रस्ताव में परिसीमन को अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रखने का भी फैसला शामिल है। यानी सीटों की संख्या में प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद उन्हें वर्ष 2051 तक स्थिर रखा जाएगा। इस अवधि में परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या में दोबारा बदलाव नहीं किया जाएगा। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब संसद में इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक के प्रावधानों और इसके लागू होने की प्रक्रिया पर आगे की स्थिति संसद में चर्चा के दौरान स्पष्ट होगी। अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया गया था। लेकिन लोकसभा में इसे पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। उस विधेयक में सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने का प्रावधान भी नहीं था। केंद्र सरकार ने गुरूवार को बताया कि उसने लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से संसद की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया है, ताकि जरूरी सरकारी कामकाज पूरा किया जा सके। लोकसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा जबकि राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संसद का यह विशेष सत्र मानसून सत्र का ही विस्तार है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था।

सरकार इस विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के साथ-साथ लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की लोकसभा में दूसरे राज्यों के मुकाबले मौजूदा हिस्सेदारी कम न हो। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को परिसीमन पर रूख एक बार फिर साफ किया। स्टालिन ने स्पष्ट किया कि परिसीमन के दौरान तमिलनाडु को मिलने वाली लोकसभा सीटों के हिस्से से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राज्य की मौजूदा 7.18 फीसदी हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए, भले ही कुल सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए।

परिसीमन पर कांग्रेस का 'ब्रेक', सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का करेगी विरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अब इंडिया ब्लॉक की बैठक भी बुलाएगी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में हुई सांसदों की बैठक में पार्टी ने अपना रूख साफ किया। कांग्रेस की यह बैठक 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले आयोजित की गई। इसमें पार्टी के सांसदों ने परिसीमन विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पत्रकारों को पार्टी के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी और इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के साथ भी चर्चा की जाएगी। पार्टी ने अपनी तीन प्रमुख मांगें दोहराई हैं, जिनके आधार पर वह सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगी। कांग्रेस की पहली मांग है कि लोकसभा की मौजूदा कुल सीटों की संख्या बरकरार रखी जाए। पार्टी चाहती है कि परिसीमन के नाम पर सदन की मौजूदा सदस्य संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाए। कांग्रेस का मानना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना जरूरी नहीं है। मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या को बनाए रखने के पक्ष में है। कांग्रेस की दूसरी मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों के भीतर ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।



जल परियोजनाओं को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की यमुना जल समझौता एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा

संबंधित विभाग समन्वय के साथ करें कार्य, जल्द से जल्द जल परियोजनाओं को किया जाए पूर्ण- मुख्यमंत्री शर्मा



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में यमुना जल समझौता एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करते हुए जनता को लाभान्वित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित अंतराल पर मौके पर पहुंचे और धरातल पर हो रही कार्य प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति, विद्युत लाइन शिफ्टिंग सहित सभी संबंधित कार्यों को लेकर विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और काम में तेजी लाएं, ताकि प्रदेश जल्द से जल्द जल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

परिसीमन बिल पर शरद पवार की पार्टी में असमंजस, सुप्रिया सुले बोलीं- ड्राफ्ट पढ़कर लेंगे फैसला



मुंबई (एजेंसी)। शरद पवार की एनसीपी (एसपी) संसद में आने जा रहे डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट करने जा रही है। यह दावा पार्टी के सांसद जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद किया है। हालांकि, इसके बाद, शरद पवार की बेटी और एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सफाई पेश की। सुप्रिया ने कहा कि बिल का ड्राफ्ट पढ़े बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हम साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आव्हाड ने शायद सीटों में 50 परसेंट बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात की थी।

मुंबई के अस्पताल में भर्ती शरद पवार से मुलाकात करने के बाद एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ऐलान किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शरद पवार के साथ अपनी बातचीत पर हृष्टक-स्कनेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, 'बातचीत हमारी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के बारे में नहीं थी। आम तौर पर यह कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस एक संवैधानिक जरूरत है। डिलिमिटेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने का फैसला किया गया है, और हम सच में इसका सपोर्ट करेंगे। हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट करेंगे।'

कई दिनों से अटकलें लग रही हैं कि शरद पवार की पार्टी डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा, डीएमके पर भी ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछले दिनों जब शरद पवार बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे, तब सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की थी और उनका हालचाल जाना था। इसके बाद अटकलें लगने लगी थीं कि शरद पवार की पार्टी आने वाले समय में एनडीए का हिस्सा बन सकती है। हालांकि, इसपर आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि एनसीपी-एसपी डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका होगा।

इंडिया अलायंस की बैठक से सुप्रिया सुले ने बनाई थी दूरी- सुप्रिया सुले ने कहा था कि वह संसद की विशेष बैठक में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को बुलाई गई 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनके पिता शरद पवार अस्वस्थ हैं। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा कि पवार के अस्पताल में भर्ती होने के कारण वह मुंबई में ही रहेंगी। उन्होंने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर लिखा, ''मैं (संसद की विशेष) बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार सुबह दिल्ली जाऊंगी।'' शरद पवार को शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के कारण गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इससे पहले, सुप्रिया सुले ने डिलिमिटेशन बिल पर कहा था कि उनकी पार्टी पहले बिल के मसौदे को पढ़ेगी और उसके बाद ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से बुलाई गई है, जिसमें जरूरी कामकाज निपटाए जाने की बात सरकार की ओर से की गई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है।

जिले की 22 पंचायत समितियों में प्रधान पद के निर्वाचन परिणाम घोषित

कांग्रेस के 16, भाजपा के 4 एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 अभ्यर्थी प्रधान पद पर निर्वाचित

जयपुर (कासं)। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में प्रधान पद के निर्वाचन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। घोषित परिणामों के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 16, भारतीय जनता पार्टी के 4 तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 अभ्यर्थी प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं। आंधी एवं शाहपुरा पंचायत समितियों में प्रधान पद के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि शेष 20 पंचायत समितियों में मतदान के माध्यम से निर्वाचन संपन्न हुआ।

उन्होंने बताया कि आंधी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 से कांग्रेस की माया देवी वर्मा तथा शाहपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 4 से कांग्रेस की संतरा गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित हुईं। अमरसर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 से कांग्रेस की समोती देवी मीणा 8 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से, आमेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 21 से कांग्रेस की कलावती 17 मत प्राप्त कर 14 मतों के अंतर से तथा बस्सी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 25 से कांग्रेस के लालाराम सैनी 21 मत प्राप्त कर 17 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चाकसू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 14 से कांग्रेस की संतोष देवी मीणा 9 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से, चौमूं पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से भाजपा के रामगोपाल मीणा 14 मत प्राप्त कर 5 मतों के अंतर से तथा दूदू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अयोध्या देवी 9 मत प्राप्त कर 3 मतों के अंतर से निर्वाचित हुईं। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस की सुमन यादव 12 मत प्राप्त कर 6 मतों के अंतर से तथा जालसू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 से भाजपा की किशन देवी 8 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से निर्वाचित हुईं।

उन्होंने बताया कि जमवारामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस के दीपक कुमार 18 मत प्राप्त कर 13 मतों के अंतर से, झोटवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 7 से कांग्रेस की मोनिका 13 मत प्राप्त कर 11 मतों के अंतर से तथा जोबनेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस की कमला देवी 13 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से निर्वाचित हुईं। किशनगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 से कांग्रेस के मदन उर्फ पप्पू 11 मत प्राप्त कर 5 मतों के अंतर से तथा कोटखावदा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस की अनोखी देवी 10 मत प्राप्त कर 5 मतों के अंतर से निर्वाचित हुईं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माधोराजपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस की प्रियंका 10 मत प्राप्त कर 6 मतों के अंतर से, मौजमाबाद पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 से भाजपा के नन्दू 10 मत प्राप्त कर 3 मतों के अंतर से तथा फागी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से कांग्रेस के कैलाश चन्द चौधरी 10 मत प्राप्त कर 5 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 5 से कांग्रेस की गीता मौर्य 8 मत प्राप्त कर 1 मत के अंतर से, सांभरलेक पंचायत समिति के वार्ड संख्या 5 से भाजपा के दशरथ सिंह 10 मत प्राप्त कर 6 मतों के अंतर से तथा सांगानेर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 5 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीमा चौधरी 11 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से निर्वाचित हुईं। तूंगा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 से कांग्रेस के रामफूल चन्द 11 मत प्राप्त कर 7 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए।

तमिलनाडु दीपम विवाद में मंदिर ट्रस्ट निलंबित; सीआरपीएफ को सौंपी सुरक्षा



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै के 'दीपथून' स्तंभ पर दीप जलाने के अपने आदेश का पालन न करने को लेकर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृष्टया यह राज्य सरकार द्वारा अदालत की अवमानना और जानबूझकर आदेश की अनदेखी का मामला है।' तिरूपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, 'शनिवार को दीपाथून पर दीप जलाएं।' सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उसके आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने मदुरै के अरूलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के ट्रस्टियों को निलंबित कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'कल दीपथून पर दीप जलाना सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट आज उन अवमानना याचिकाओं और अन्य आवेदनों पर सुनवाई कर रहा था, जो 'दीपथून' स्तंभ पर पारंपरिक दीप न जलाए जाने से जुड़े विवाद के संबंध में दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बावजूद, 24 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम' केवल तिरूप्परनकुंद्रम के पारंपरिक 'उचि पिल्लयार मंडपम' में जलाया गया, न कि 'दीपथून' पर। सुनवाई शुरू होते ही, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मुख्य मामले में नहीं जाएगी, बल्कि अपना ध्यान केवल 20 नवंबर के उस आदेश के उल्लंघन पर केंद्रित रखेगी, जिसमें 24 नवंबर को एक बार के उपाय के तौर पर 'दीपथून' पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को 'दीपथून' पर पारंपरिक दीप न जलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी और इसके लिए अरूलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। याचिकाकर्ताओं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील ने इसे 'गंभीर अवमानना' का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से ट्रस्टियों को हटाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्टियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। एएसआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा, 'मेरी मांग है कि जिन लोगों पर अवमानना का आरोप है, उनकी बात सुनने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि दीपक उसी जगह जलाया जाए, जहां उसे जलाया जाना था।' कोर्ट ने कहा, 'प्रशासन का बर्ताव अदालत के आदेश की जानबूझकर और बेशर्मी से की गई अवहेलना को दिखाता है। अदालत ने कहा कि मदुरै के जिला कलेक्टर, एचआर एंड सीई विभाग के डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बनता है, जिनकी भूमिका रिकॉर्ड से स्पष्ट होती है। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे 'दीपक' (दीपम) मामले से जुड़ी बैठकों, संदेशों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जानकारी देते हुए एक हलफनामा दाखिल करें।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संस्थापक - स्व. डॉ. विश्वबन्धु जी त्रिवेदी

भ्रम के सहारे चलती जिंदगी और सियासत

- राधा शर्मा -

जिंदगी गुजारने के लिए कोई न कोई भ्रम पालना जरूरी है। जिसने कोई भ्रम नहीं पाला, समझिए उसने जिंदगी का एक अहम विषय ही खो दिया। देश का बहुत कुछ गलतफहमियों के सहारे चल रहा है। बल्कि आवाम को चलाने के लिए वही हुक्मरान बेहतर माना जाता है, जो समय-समय पर झूठे भरोसे बांटता रहे। यही वजह है कि लोग धर्म के भ्रम और कर्म की गलतफहमी में ही उसे श्रेष्ठ मान लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के सामने अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ठीक-सी उम्मीद चुनना भी बहुत कठिन होता है। शायद इसीलिए वह अक्सर पीछे रह जाता है।

हर चुनाव में कोई न कोई आम आदमी को वोट देने के अधिकार के नाम पर नई उम्मीद जरूर दिखा देता है। आजादी के बाद से आम आदमी इसी उम्मीद के सहारे सरकारें चुनता आ रहा है, लेकिन अंत में सरकारों का कार्यकाल ही उसके लिए एक नई निराशा बन जाता है। भ्रम दरअसल बांझ गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया जैसा है। देश में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि गंजे का मुंडन करना सबसे आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। गंजे के बचे हुए बालों को समेटना भी इतना आसान नहीं कि कोई यूं ही उसे मूंडकर चला जाए।

अब तो देश में ऐसे गरीब भी पैदा होने लगे हैं, जिनसे बैंक तक डरने लगे हैं। न अमीर को कोई भ्रम होता है और न गरीब को, बल्कि मध्यमवर्गीय परिवार ही तरह-तरह की खुशफहमियों में जीते हैं। ये लोग सरकारें बदलकर वर्षों से अपनी जीत तलाश रहे हैं। मिडिल क्लास का पहला भ्रम अपनी तनख्वाह पर, दूसरा बैंक की बचत पर, तीसरा औलाद के भविष्य पर और चौथा भगवान पर टिका होता है। अब तो स्वतंत्रता भी एक तरह की खुशफहमी बनती जा रही है, हालांकि यह एक अच्छी खुशफहमी है। दफ्तर में साहब और घर में पत्नी को यह गलतफहमी बनी रहे कि आपसे स्वतंत्र उनके अपने अधिकार हैं, तो आप दफ्तर से घर तक राज कर सकते हैं। मीडिया भी अपनी स्वतंत्रता को लेकर इस खुशफहमी में है कि पत्रकारिता उसके अपने तय किए पैमानों पर ही आगे बढ़ रही है। खैर, एक दिन राजा को भी यह गलतफहमी हो गई कि प्रजा केवल उसी के कथनों पर विश्वास करती है। अपना दबदबा कायम रखने के लिए राजा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो उसकी बात न माने, उसका मुंडन कर दिया जाए।

आश्चर्य यह कि मजदूर को न्यूनतम दिहाड़ी और किसान को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आजादी के बाद पहली बार जो उम्मीद दिखाई गई थी, वह आज भी कायम है। उम्मीद जितनी न्यूनतम होती है, उसका असर उतना ही घातक हो सकता है। देखते ही देखते देशभर के कई लोगों के मुंडन हो गए। हालात ऐसे बने कि लोगों को राजा से ज्यादा अपने ही बचे हुए बालों का खौफ सताने लगा। लेकिन मुसीबत यह हुई कि गंजों के खिलाफ राजा के नाई कुछ नहीं कर पा रहे थे। ईमानदार, शरीफ, ज्ञानी, रसूखदार और मिलनसार गंजों के बीच कई लोग राजा के तौर-तरीकों के खिलाफ थे।

राजा ने काफी सोच-विचार के बाद फैसला किया कि अब कोई भी गंजा नंगे सिर नहीं घूमेगा। कुछ ही दिनों में सारे गंजे पगड़ीधारी हो गए। लेकिन जनता के मन में अब एक नई शंका पैदा हो गई कि पगड़ी के नीचे कहीं राजा भी तो गंजा नहीं है। उधर राजा इस खुशफहमी में था कि उसके राज्य में अब कोई भी गंजा बदनाम नहीं होगा। दरअसल, भ्रम और खुशफहमी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को देखने के बजाय वही देखना चाहता है, जो उसे अच्छा लगता है। जनता को लगता है कि वह सब समझ रही है और राजा को विश्वास होता है कि जनता कुछ नहीं समझ रही।

दोनों अपनी-अपनी गलतफहमी में जीते रहते हैं। लेकिन जब कभी हकीकत सामने आती है, तो सबसे पहले वही भ्रम टूटता है, जिसे सबसे मजबूत समझकर पाला गया होता है। विडंबना यह है कि भ्रम का बाजार जितना बड़ा होता है, सच की कीमत उतनी ही कम होती जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से सच का अर्थ निकालने लगा है। कोई अपनी असफलता को परिस्थितियों के सिर मढ़ देता है, तो कोई दूसरों की सफलता को किस्मत का खेल बताकर खुद को तसल्ली देता है। सत्ता को भी ऐसे ही भ्रम पसंद आते हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाली जनता से ज्यादा आसान उन लोगों को संभालना होता है, जो हर जवाब को उपलब्धि समझकर तालियां बजाते रहें।

समाज में सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है, जब उम्मीद और हकीकत के बीच का अंतर ही खत्म हो जाए। आदमी अपनी परेशानियों को नियति मान ले और व्यवस्था की खामियों को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। फिर न उसे सवाल पूछने की जरूरत महसूस होती है और न जवाब मांगने की। लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार केवल वोट देना नहीं, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों से उनके वादों का हिसाब मांगना भी है। वरना हर पांच साल बाद नए भ्रम की पगड़ी बांधकर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती रहेगी। सच तो यह है कि भ्रम में जीना आसान हो सकता है, लेकिन हकीकत से आंख मिलाने का साहस ही समाज को आगे ले जाता है।

एक व्यक्ति के भरोसे एआई की दुनिया, कितना सुरक्षित भविष्य?

भारत के नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत को इस घटनाक्रम से यह भी समझना चाहिए कि तकनीकी विकास केवल बड़ी कंपनियों और उनके प्रभावशाली प्रमुखों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। किसी भी महत्वपूर्ण तकनीक की आपूर्ति यदि कुछ गिनी-चुनी कंपनियों तक सीमित हो जाए, तो उसका असर पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ सकता है। एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए भारत को अपने शोध संस्थानों, स्टार्टअप और घरेलू चिप निर्माण क्षमता में निवेश बढ़ाना होगा। साथ ही, बड़ी कंपनियों के बोर्ड को यह साबित करना होगा कि वे किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता से ऊपर उठकर संस्थागत हितों को प्राथमिकता देते हैं। शेयर बाजार में किसी नेता की वापसी पर तेजी आना निवेशकों के उत्साह का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे सुशासन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कंपनियों की असली मजबूती संकट के समय उनके नियमों, पारदर्शिता और जवाबदेही से सामने आती है। एआई की दौड़ में आगे निकलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके आर्थिक और नैतिक जोखिमों को समझना भी है। भारत को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीक के साथ भरोसा और जवाबदेही भी मजबूत हों। अंतत: किसी भी कंपनी का भविष्य उसके एक चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी मजबूत संस्थाओं और दूरदर्शी नीतियों से तय होना चाहिए। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक है। एनवीडिया के नए चेयरमैन हार्वे जोन्स ने निवेशकों से कहा था कि बोर्ड ने जेनसन हुआंग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें वापस लाने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस सोमवार बोर्ड उन्हें वापस ले आया। फैसला सर्वसम्मति से हुआ और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। हुआंग फिर से अध्यक्ष, सीईओ और बोर्ड सदस्य हैं। एक ही दिन में शेयर 31 फीसदी चढ़ गया। इससे काफी हद तक पता चल जाता है कि यह वापसी कौन चाहता था।

यह याद रखना जरूरी है कि वे गए कैसे थे। पहले खबरें आईं कि उनकी एक ऐसी महिला से नजदीकी थी, जिसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना था कि वह बीजिंग के लिए काम कर रही थी। फिर दूसरे प्रेम-संबंधों की खबरें आईं, जिनमें एक ऐसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंध भी था, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थीं। ज्यादातर कंपनियों में यहीं कॅरियर खत्म हो जाता। एनवीडिया में यह ग्यारह दिन का ब्रेक भर साबित हुआ।

बोर्ड का बयान अधिक कुछ नहीं बताता। उसमें कहा गया है कि इस मामले में काफी बातचीत के बाद बोर्ड हुआंग की स्पष्टवादिता से संतुष्ट है। यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ लोगों ने भरोसा दिलाया कि उनकी वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इस दूसरी बात को ध्यान से पढ़िए। इसमें यह नहीं कहा गया कि कुछ गलत नहीं हुआ। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि उन्हें वापस लाने से हालात और नहीं बिगड़ेंगे। कहीं कुछ लीक तो नहीं हुआ, इसकी स्वतंत्र जांच अब भी चल रही है। यानी असल में बोर्ड ने एक व्यक्ति को यह पता लगाए बिना दोबारा रख लिया है कि उसने किया क्या था।

ऐसा क्यों हुआ? कुछ कारण तो साफ हैं। हुआंग के पहली बार गलती मानने और उनकी वापसी के बीच एनवीडिया की लगभग एक-तिहाई कीमत डूब गई। यह सैकड़ों अरब डॉलर

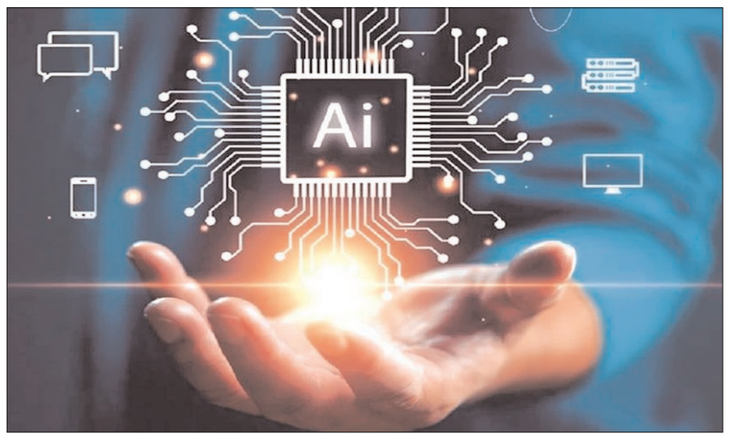

की रकम है, और बोर्ड शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। हुआंग जितने दिन बाहर रहे, बाजार हर दिन एक ही संदेश देता रहा और उसकी आवाज तेज भी होती गई। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी वजह यह है कि एनवीडिया अब सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है। पिछले दो-एक वर्षों में वह चुपचाप पूरी एआई इंडस्ट्री के लिए एक तरह के बैंकर की भूमिका में आ गई है। जो एआई लैब उसकी चिप खरीदती हैं, उनमें उसकी हिस्सेदारी है। जो नई क्लाउड कंपनियां डाटा सेंटर बनाकर कंप्यूटिंग पावर किराये पर देती हैं, उनमें वह पैसा लगाती है। चार-पांच साल बाद जब इन डाटा सेंटरों की चिप बदलनी होंगी, तो सबको उम्मीद है कि नई चिप भी एनवीडिया की ही होंगी।

यह बेहद मुनाफे वाली व्यवस्था है, लेकिन यह कुछ हद तक एक चक्र की तरह भी है : वही कंपनी हार्डवेयर बनाती है, वही ग्राहकों को पैसा देती है और वही मांग को सहारा भी देती है। ऐसी व्यवस्था लोगों के भरोसे पर टिकी रहती है, और पिछले कुछ वर्षों से उस भरोसे का एक ही चेहरा रहा है। खबरों के मुताबिक, बैंक पहले से ही डाटा सेंटर के ऐसे कर्जों में फंसे थे, जिन्हें वे आगे बेच नहीं पा रहे थे। एआई कंपनियां अब भी अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर रही हैं। कोई अंतरिम सीईओ, चाहे कितना भी काबिल हो, किसी को आश्वस्त नहीं कर पाता।

फिर उनका रिकॉर्ड है, जिस पर बहस करना मुश्किल है। बीस साल पहले हुआंग ने अरबों डॉलर लगाकर क्यूडा बनाया, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिससे गेमिंग चिप गंभीर कंप्यूटिंग का काम कर सकीं। बहुत लोगों को लगा कि एक छोटे-से अकादमिक दायरे पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, और कंपनी के शेयर ने बरसों तक इसकी कीमत चुकाई। आज एनवीडिया जहां है, उसकी सबसे बड़ी वजह वही फैसला है।

क्या कंपनी उनके बिना चल पाती? बिल्कुल। बोर्ड बस यह परखना नहीं चाहता था कि कितनी अच्छी तरह। फिर वाशिंगटन भी है। वोटिंग से एक रात पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बोर्ड से हुआंग को वापस लेने को कहा। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से 'प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से' बात की थी। फैसले का स्वागत करने वाली उनकी पोस्ट कुछ ही मिनटों में आ गई। एनवीडिया को चलने के लिए निर्यात लाइसेंस और राजनीतिक सद्भाव, दोनों चाहिए। वहां कोई भी इस इशारे को नजरअंदाज नहीं करने वाला था।

इसमें से कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है। मुझे परेशानी इस बात से है कि इस मामले ने हमें कहां पहुंचाया है। एक निजी कंपनी ने अपना सीईओ कुछ हद तक इसलिए चुना, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि सब ठीक है, जबकि खबरों के मुताबिक, उसी सरकार के नियामक अब भी कंपनी की जांच कर रहे हैं। अगर सरकार किसी की गारंटी लेकर उसे वापस ला सकती है, तो वह किसी को बाहर भी करवा सकती है।

निवेशकों ने यह भी सीख लिया है कि एआई की सबसे अहम कंपनी को उसकी अपनी गलतियों से बचा लिया जाएगा। जब लोगों को लगता है कि कोई उन्हें गिरने से थाम लेगा, तो वे बड़े जोखिम उठाते हैं। इस तेजी ने यह असली सवाल हल नहीं किया कि एआई पर हो रहा यह सारा खर्च आखिर फायदा देगा या नहीं। दिसंबर की शुरूआत में वाशिंगटन में होने वाली सुनवाईयां इसका जवाब तलाशना शुरू कर सकती हैं।

पूर्व संध्या पर आयोजन स्थल पर तैयारियों को दिया अंतिम रूप

आज से सजेगा पक्षियों का रंगीन संसार, देशभर के पविशेषज्ञों का जुटना शुरू

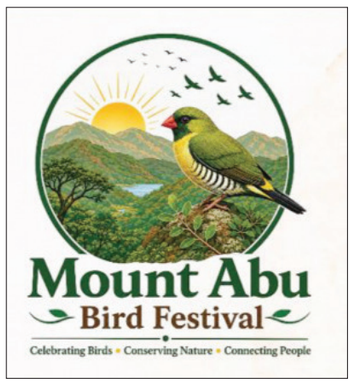



उदयपुर-माउंट आबू। अरावली की सुरम्य वादियों में बसे राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कल से पक्षियों और जैव विविधता का अनूठा उत्सव शुरू होगा। पहली बार आयोजित हो रहे दो दिवसीय 'माउंट आबू बर्ड फेस्टिवल-2026' में शामिल होने के लिए देशभर से पविज्ञानी, बर्ड एक्सपर्ट, वन्यजीव विशेषज्ञ और प्रकृतिप्रेमी पहुंचने लगे हैं। 28 और 29 नवंबर को आयोजित होने वाले इस महोत्सव में करीब 400 विद्यार्थी भी भाग लेंगे। ग्रीन पीपल सोसायटी (जीपीएस), उदयपुर के तत्वावधान में राजस्थान वन विभाग, सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा अकादमी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सहयोग से होने वाले इस आयोजन की पूर्व संध्या पर सोसायटी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त सीसीएफ राहुल भटनागर, उपाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस विक्रम सिंह तथा प्रतिनिधिमंडल ने आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयोजन व्यवस्था प्रभारी प्रो. इंद्रजीत माथुर ने प्रतिनिधिमंडल को विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई विशेष किट, उनके आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। विद्यार्थियों की सहभागिता को महोत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, बर्ड वॉक और बर्ड ट्रेल जैसी गतिविधियां होंगी, जिनके माध्यम से वे पक्षियों की पहचान और उनके संरक्षण के व्यावहारिक पहलुओं को समझ सकेंगे। महोत्सव का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा अकादमी में होगा। उद्घाटन समारोह में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. वीरेंद्र सिंह जाटावत, राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आईएफएस शशि शंकर पाठक सहित प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित तकनीकी सत्र में पविज्ञानी डॉ. रजत भार्गव राजस्थान में संकटग्रस्त ग्रीन अवदावत के संरक्षण, डॉ. सुतिर्था दत्ता ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, संगीतकार एवं वन्यजीव संरक्षणकर्ता अभिषेक रे 'बाघ : द इनसाइड स्टोरी' तथा वन्यजीव जीवविज्ञानी विजयादित्य सिंह राठौड़ थार मरुस्थल में कृषि परिवर्तन और जैव विविधता पर व्याख्यान देंगे।

250 से अधिक पप्रजातियों की विरासत पर होगा मंथन

माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में 250 से अधिक पप्रजातियां दर्ज हैं। ग्रीन मुनिया, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और इंडियन पिट्टा जैसी प्रजातियां यहां की समृद्ध पविविधता को दर्शाती हैं।

महोत्सव में अरावली क्षेत्र के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण, पक्षियों की घटती संख्या, जैव विविधता और प्रकृति आधारित पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी।

क्षेत्र के प्रकृतिविद् एवं पप्रेमी स्वर्गीय अनिल माथुर की स्मृति को समर्पित इस महोत्सव का उद्देश्य माउंट आबू की प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और नई पीढ़ी को संरक्षण के अभियान से जोड़ना है।

आयोजकों की योजना इसे वार्षिक आयोजन के रूप में विकसित करने की है, ताकि पगणना, विद्यालयों में बर्ड क्लब और नागरिक विज्ञान जैसी गतिविधियों को भी निरंतर बढ़ावा मिल सके।

उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था बदलने का समय, डीबीटी से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ



भारत में बड़ी तादाद में पशु धन है और जैविक खाद के उत्पादन के लिए अभी तक अधिक प्रोत्साहन नहीं होने के कारण पशुधन का गोबर बेकार चला जाता है। लेकिन किसान को उर्वरक सबसिडी प्रत्यक्ष रूप से मिलने के कारण, वे जब जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जैविक खाद के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन होगा और देश में गोबर का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसका तीसरा लाभ यह होगा कि जैविक खाद का उत्पादन ज्यादा होने के कारण किसान गोबर के लिए ज्यादा पशु रखना चाहेंगे। इससे देश में डेयरी उत्पादन भी बढ़ सकेगा, जिससे किसान की आमदनी और बढ़ सकेगी। चौथे, रासायनिक उर्वरकों पर सबसिडी के चलते इन उर्वरकों का वैज्ञानिक और आर्थिक आधार पर इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता और देश के संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यदि किसान के खाते में सबसिडी पहुंचे तो वह अधिक वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करेगा। पांचवां, सबसिडी के बल पर कृषि भूमि पर ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अन्य पोषक तत्व (न्यूट्रिएंट्स), जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, की लगातार कमी हो रही है। गौरतलब है कि कृषि को अनेक (लगभग 16) प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाद के रूप में आवश्यक हैं। लगातार कृषि करने से उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की भरपाई करना जरूरी हो जाता है, लेकिन सरकार की वर्तमान सबसिडी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ ही न्यूट्रिएंट्स की भरपाई संभव हो पाती है। अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के खाते में सीधे सबसिडी देकर, हम कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे मुख्य रूप से आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आयातित उर्वरकों पर खर्च होती है और यह खर्च हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2025-26 में, रासायनिक उर्वरकों का कुल आयात 14.2 अरब अमरीकी डॉलर था।

हालांकि यह सच है कि वर्तमान प्रणाली ने उर्वरकों की उपलब्धता और उन्हें किफायती बनाए रखना सुनिश्चित किया है, फिर भी इसे और अधिक पारदर्शी, कुशल और किसान-केंद्रित बनाने की गुंजाइश है। भुगतान प्रणाली में पिछले एक दशक में आए सुधारों के कारण अब सरकार धीरे-धीरे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) प्रणाली की ओर बढ़ सकती है।

जिसके तहत पात्र उर्वरक सबसिडी सीधे किसानों के बैंक खातों या डिजिटल उर्वरक वॉलेट में जमा हो सके। सत्यापित खेती के रिकॉर्ड और बैंक खातों से जोड़ते हुए प्रत्येक पात्र किसान को एक डिजिटल उर्वरक सबसिडी कार्ड दिया जा सकता है। सबसिडी की पात्रता का निर्धारण खेती के रकबे, फसल पैटर्न, मौसम और पोषक तत्वों की अनुशंसित आवश्यकताओं के आधार पर तय हो सकता है। इसमें बटाईदार किसानों और पट्टे पर खेती करने वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सबसिडी की राशि बुवाई के मौसम से पहले ही खाते में जमा करने वाला प्रावधान हो तो किसान बाजार मूल्य पर उर्वरक खरीद सकेंगे। इस प्रणाली को सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ताकि पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिले और स्वीकृत जैविक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों तथा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाले अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से बढ़े तो बेहतर होगा। पहले चरण में बटाईदार किसानों को भी शामिल करते हुए, किसानों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, खेती का विवरण, बैंक खाते और सॉइल हेल्थ कार्ड शामिल हों। दूसरे चरण में पायलट कार्यान्वयन हो सकता है जिसमें चुनिंदा जिलों में प्रत्यक्ष सबसिडी हस्तांतरण शुरू किया जा सकता है। तीसरे चरण में पायलट कार्यान्वय के संदर्भ में डीबीटी के वित्तीय प्रभावों, किसानों की संतुष्टि, उर्वरकों की उपलब्धता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और संभावित लीकेज आदि आकलन किया जा सकता है। अंतिम चरण में इस योजना का विस्तार हो। भारत में कृषि सबसिडी के कई प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार, इनपुट सबसिडी है। इनपुट सबसिडी में, उर्वरक सबसिडी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल कृषि सबसिडी 414614 करोड रुपए रही, जिसमें उर्वरक सबसिडी 186460 करोड रुपए रही। उर्वरक सबसिडी में अधिकांश न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी है और एक अन्य प्रकार यूरिया सबसिडी है। इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी के लिए 41533.81 करोड रुपए का प्रावधान केंद्रीय कैबिनेट ने किया, जो कि पिछले खरीफ मौसम (2025) में 37216.15 करोड रुपए से 4317.66 करोड़ रुपए अधिक था। रबी के मौसम के लिए न्यूट्रीएंट आधारित सबसिडी की घोषणा अभी बाकी है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष सबसिडी व्यवस्था लागू होने से उर्वरक बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिल सकता है। किसान अपनी जरूरत और खेत की मिट्टी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के उत्पाद चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इससे उर्वरक कंपनियों को भी गुणवत्ता सुधारने और उचित कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना पड़ेगा। सरकार के लिए भी सबसिडी के वास्तविक लाभार्थियों और खर्च का आकलन करना आसान होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले कुछ व्यावहारिक चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो दूसरों की जमीन पर बटाई या किराये से खेती करते हैं, लेकिन सरकारी भूमि रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होता। इसलिए सबसिडी का लाभ केवल जमीन के मालिकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महिला किसानों और छोटे तथा सीमांत किसानों की जरूरतों को भी विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करना होगा। किसानों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सबसिडी मिलने के बावजूद बाजार में उर्वरकों की कृत्रिम कमी और जमाखोरी की स्थिति पैदा न हो। शुरुआत में रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार के उर्वरकों के लिए संतुलित विकल्प उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इस तरह प्रत्यक्ष सबसिडी केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार का आधार बन सकती है। जरूरत इस बात की है कि किसान को सबसिडी का वास्तविक लाभ मिले और वह अपनी खेती से जुड़े फैसले आर्थिक स्वतंत्रता के साथ कर सके।

वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सबसिडी के लिए 116799 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। पहले तो उर्वरक सबसिडी देने का तरीका भिन्न था, लेकिन वर्ष 2010 में इसे न्यूट्रिएंट आधारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार चार पोषक तत्वों-नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, के आधार पर सबसिडी निर्धारित करना शुरू किया गया। ऐसा समझा गया कि न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने से उर्वरकों का संतुलित उपयोग होगा, मृदा यानी मिट्टी की सेहत बेहतर होगी और घरेलू उर्वरकों का उपयोग बढ़ेगा। लेकिन देखा गया कि उसके बावजूद कंपनियों के माध्यम से उर्वरक सबसिडी बदस्तूर जारी रही, आयातों पर निर्भरता बढ़ती रही और घरेलू उर्वरकों का उपयोग नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2010 से पहले भी और 2010 में न्यूट्रिएंट आधारित सबसिडी देने के बाद भी सबसिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि कंपनियों को दी जाती रही है। कंपनियों को सबसिडी उनके द्वारा बिक्री किए गए उर्वरकों के आधार पर दी जाती है। किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सबसिडी से लाभ किसानों को कम और कंपनियों को ज्यादा होता है। उर्वरक कंपनियां चाहे सहकारी क्षेत्र में हों, सरकारी हों अथवा निजी क्षेत्र में, सभी के लाभ ऊंचे बने हुए हैं और किसानों की मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। उसको समय पर उर्वरक नहीं मिलते हैं और अन्यान्य कारणों से उसकी लागत तो लगातार बढ़ ही रही है, उसके लाभ कम होते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कृषि लाभ का सौदा नहीं रही। लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि उर्वरक सबसिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए, न कि कंपनियों के माध्यम से। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। पूर्व में सभी प्रकार की सबसिडी व्यावहारिक कारणों से अप्रत्यक्ष रूप से मिलती थी और बिचैलियों के कारण लाभार्थी को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आज तकनीकी विकास से यह संभव हो सका है कि विभिन्न प्रकार की सबसिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच सके। जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल बैंकिंग यानी 'जैम त्रे' के कारण ऐसा संभव हो सका है। किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के खाते में पहुंच रही है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग हो रही है जिससे किसानों को उर्वरक सबसिडी भी सीधे तौर पर पहुंच सके। यदि ऐसा संभव हो सके तो किसानों को तो फायदा होगा ही, क्योंकि लगभग वो हिस्सा जो कंपनियों के खाते में जाता है।

सोने से पहले तलवों की करें मालिश, मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे



चेहरे की देखभाल तो सभी कर लेते है लेकिन पैरों की तरफ ध्यान देना अक्सर भूल जाते है। जिन पर हम लोग सारा दिन खड़े रहते है उनकी अच्छे से देखभाल होना भी जरूरी है। इसके अलावा हमारे पैरों के विभिन्न प्वाइंट अलग-अलग अंगों से जुड़े होते है। अगर इन प्वाइंट की रात को मालिश की जाए तो यह शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते है। हम आपको बताएंगे कि रात को पैरों की मालिश करने से कौन-कौन से फायदे मिलते है।

मेटाबॉलिज्म

अगर सोने से पहले पैरों के तलवे पर अच्छे से 10-15 मिनट मालिश की जाए तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है।

वजन कम

बढ़ते वजन की समस्या आज हर व्यक्ति को परेशान कर रही है। अगर रात को पैरों की तलवों को मालिश की जाए तो इससे वजन के साथ-साथ शरीर में मौजूद वसा भी कम होती है।

तनाव और थकावट

दिनभर काम के बोझ के चलते स्ट्रेस और तनाव जैसी समस्या घेरे रहती है। इससे बचने के लिए पैरों के तलवों की मालिश करें। इससे शरीर रिलेक्स महसूस करेगा और अच्छी नींद आएगी।

रक्तचाप नियंत्रित

हाई ब्लड प्रेशन के मरीजों के लिए यह प्रक्रिया काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। बस रोज रात को सोने से पहले नारियल या बादाम के तेल से तलवों की मालिश करे।

सेक्स लाइफ में सहायक

यह प्रक्रिया आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर बना देगी।

रोजाना की इन गलतियों के कारण आप हो सकते हैं बहरे

कान हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। कानों के जरिए ही हम लोगों की आवाज सुन सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही सुनने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है लेकिन आजकल तो कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल और लोगों की कुछ गलतियों की वजह से उनमें बहरेपन की समस्या देखी जाती है। ऐसे में खुद के कानों को स्वस्थ रखने के लिए इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आइए जानिए रोजाना में की गई कुछ गलतियां जो कानों को खराब कर रही हैं।

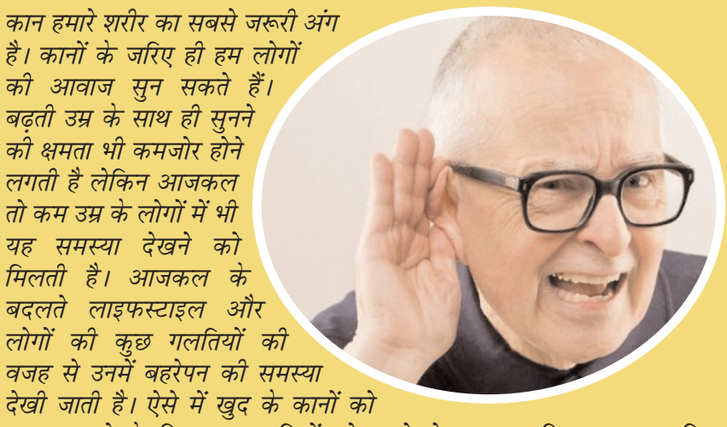





हैडफोन का इस्तेमाल

फोन पर गाने सुनना आजकल यंग जैनरेशन की पहली पसंद है। जो लोग रोजाना लंबे समय तक ईयरफोन पर ऊंची आवाज में गाने सुनते हैं। उनके ईयर ड्रम को काफी नुकसान पहुंचता है जिससे बहरेपन की समस्या हो जाती है।

बुढ़ापा

बढ़ती उम्र भी कानों के बहरेपन की मेन वजह है। उम्र बढ़ने से कानों की नर्व्स कमजोर हो जाती हैं जिससे यह समस्या हो जाती है।

कान का मैल

सही तरीके से कान की सफाई न करने की वजह से इनमें मैल जम जाता है और अगर लंबे तक कानों में मैल जमी रहे तो इससे इंफैक्शन का खतरा बढ़ जाता है जिससे बहरापन हो जाता है।

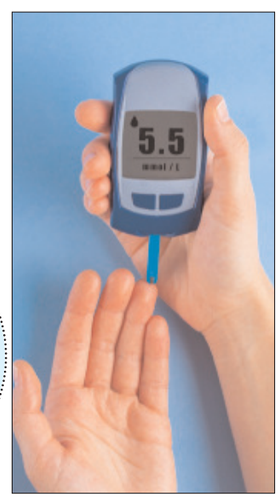

डायबिटीज



जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है उनमें भी बहरापन देखा जा सकता है। डायबिटीज की वजह से रोगियों में न्यूरोपैथी प्रॉब्लम हो जाती है और कान खराब हो जाते हैं।

कानों में इंफैक्शन



कानों की सही तरह से देखभाल न करने की वजह से इंफैक्शन हो जाती है जिससे ईयर ड्रम पर बुरा असर पड़ता है और सुनाई देना कम हो जाता है।

आर्मपिट की गांठ का इन घरेलू तरीकों से करें इलाज

कुछ लोगों के अंडर आर्म्स के बीच में गांठ पड़ जाती है जिससे सूजन और दर्द महसूस होता है। इस गांठ की वजह से अंडर आर्म्स और ब्रैस्ट के आसपास हाथ लगाने पर ही दर्द होती है। शरीर में किसी तरह की इंफैक्शन हो जाने की वजह से गांठ बन जाती है जोकि ज्यादा खतरनाक समस्या नहीं है लेकिन इसका सही समय पर इलाज न करवाया जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। ऐसे में जब भी कभी आपको बगलों में गांठ जैसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, नहीं तो कुछ घरेलू उपाय करके भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानिए ऐसे ही कुछ आसान देसी नुस्खों के बारे में

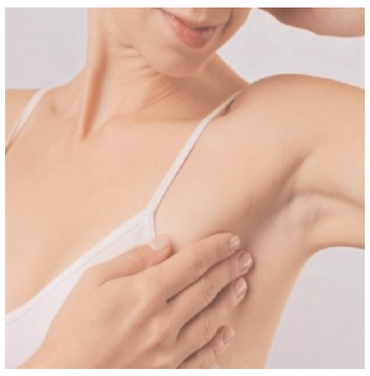

मसाज करें

इसके लिए नारियल तेल या जैतून के तेल से अंडरआर्म्स की कुछ मिनटों तक मसाज करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और गांठ से भी छुटकारा मिलेगा।

विटामिन ई कैप्सूल

शरीर में विटामिन की कमी के कारण भी आर्मपिट में गांठ हो सकती है। ऐसे में रोजाना विटामिन ई का एक कैप्सूल लें और विटामिन युक्त आहार लें।

तरबूज

आर्मपिट की गांठ को ठीक करने के लिए तरबूज का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडैंट होते हैं जो शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालते हैं। रोजाना तरबूज या इसके जूस का सेवन करने से गांठ दूर होगी और सूजन व दर्द से भी राहत मिलेगा।

नींबू का रस

नींबू में काफी मात्रा में विटामिन सी और एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं जो गांठ और सूजन को कम करते हैं। इसके लिए नींबू के रस में थोड़ा-सा पानी मिलाकर रूई की मदद से इस मिश्रण को गांठ पर लगाएं। सूखने के बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें जिससे कुछ ही दिनों में गांठ से राहत मिलेगी।

अखरोट

अखरोट में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर को हर तरह की इंफैक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे में आर्मपिट की गांठ और दर्द से राहत पाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अखरोट के पाउडर में शहद और पानी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इस ड्रिंक को रोजाना पीने से आराम मिलेगा।

महिलाओं की सेहत के लिए वरदान है मंगलसूत्र!



भारतीय संस्कृति में मंगलसूत्र महिला के सुहाग की निशानी माना गया है। यह नवविवाहित दुल्हन को शादी के दौरान पहनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनने से सेहत को कई फायदे होते हैं। हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को छिपा कर पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह जितना शरीर को स्पर्श करेगा, उतना ही फायदा देगा।

मंगलसूत्र पहनने के फायदे

- मंगलसूत्र पहनने से महिलाएं सकारात्मक महसूस करती हैं।
- इसमें मौजूद काले मोती और सोना महिलाओं के लिए लाभदायक होते है।
- मंगलसूत्र या इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है।
- आयुर्वेद के अनुसार, गले में स्वर्णधातु धारण करने से छाती और हृदय स्वस्थ रहते हैं।
- यह पति-प ी के संबंधों में गहराई लाने का भी काम करता है।

नाइट शिफ्ट में बढ़ गया है वजन तो इस आहार से करें कम

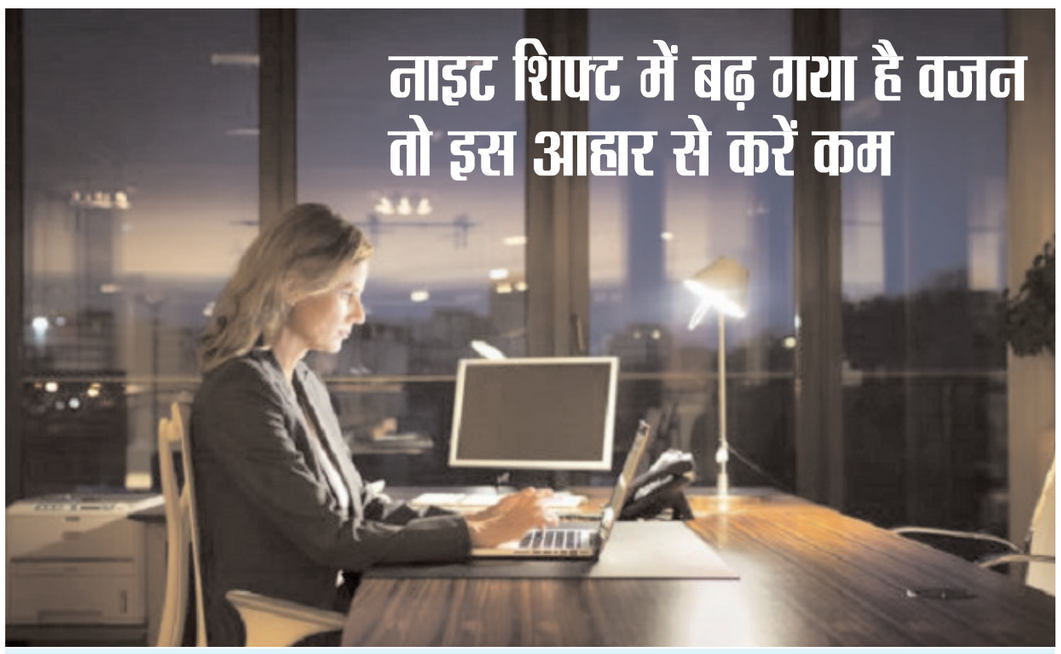

अक्सर रात को काम करने वाले लोगों का वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने से आपको तनाव, हार्ट प्रॉब्लम और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक शोध के द्धारा इस बात को सामने लाया गया कि रात को काम करने वाले लोगों का वजह 55 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि नाइट शिफ्ट में काम करते-करते भी आप किन फूड्स के जरिए अपना वजन घटा सकते है।

सलाद

नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को अधिक से अधिक सैलेड का सेवन करना चाहिए। फल या सब्जियों का सलाद खाने से आपको नजह बढ़ने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पोषक तत्व से भरपूर चीजें

रात में काम करते समय आप स्नैक्स बादाम, मुरमुरा और अलसी के बीज का सेवन कर सकते है। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा।

ब्राउन राईस

रात को भोजन में व्हाइट राइस की बजाए ब्राउन राईस खाएं। इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसमें मौजूद आयरन, जिंक, प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम ऐपको ताकत देते है और वजन बढ़ने से रोकते है।

ओट्स तथा दूध

जिन लोगों को रात में काम करना पड़ता है उन्हें नाशते में दही, ओट्स तथा दूध का स्वन करना चाहिए। वजह कम करने के लिए यह सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है।

स्प्राउट्स

इस तरह के अनाज में कैलोरी और फैट कम मात्रा में पाया जाता है। इससे आपकी भूख भी मिट जाती है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए यह सबसे अच्छा भोजन है।

बंद नाक से हैं परेशान तो अपनाएं ये टिप्स

नाक का बंद होना आम परेशानी है। कुछ लोगों को सुबह तो कुछ लोगों के मिट्टी से एलर्जी होने के कारण यह समस्या झेलनी पड़ती है। नाक के अंदर झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण यह दिक्कत आती है। सही समय पर बार-बार नाक बंद होने की तरफ ध्यान न दिया जाए को यब परेशानी और भी बढ़ सकती है। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोंस में बदलाव, डस्ट माइट यानि नाक में मिट्टी के छोटे-छोटे कणों का प्रवेश कर जाना, धुआ,परफ्यूम की खुशबू,पालतू जानवरों के बाल,मौसम में बदलाव आदि। जिन लोगों को नाक बंद होने की शिकायत होती है, उन्हें छींके आना,सिर का भारीपन, नाक में से पानी बहने जैसी मुश्किले भी झेलनी पड़ सकती है।



बंद नाक खोलने के घरेलु उपचार

भाप

नाक बंद होने पर भाप लेना सबसे अच्छा तरीका है। एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें। इस पानी से भाप ले और सिर को तौलिए से ढक दें। अजवाइन की जगह पर पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं।

सरसों का तेल

बंद नाक को खोलने के लिए उंगुली पर सरसों का तेल लगाकर सूघने से नाक तुरंत खुल जाएगी।



अजवाइन

अजवाइन को तवे पर गर्म करके भून लें और इसे पोटली में बांधकर सूघने से बंद नाक खुल जाती है।

बादाम

शरीर में कमजोरी के कारण भी बार-बार नाक बंद हो सकती है। इसके लिए 100 ग्राम बादाम,20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम शक्कर को मिलाकर पीस लें। इस पाउडर का 1 चम्चम रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ खाएं। लगातार इसका सेवन करने से छींके,बंद नाक और नाक बहने की परेशानी दूर हो जाती है।

हल्दी और लहसून

1 कप पानी में लहसून की 1 कली और 1 चुटकी हल्दी डालकर गर्म कर लें। इस पानी को छानकर चुस्की लेते हुए पीएं। इससे बंद नाक खुल जाती है।

हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दवाई नहीं करें यह योगासन





सुखासन एक बेहद आसान आसन है। इसका अभ्यास करने के लिए पहले आप जमीन पर बैठ जाएं। इस दौरान आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अब गहरी सांस अंदर की ओर लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इस दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका ध्यान आपकी श्वसन क्रिया पर होना चाहिए। आज के समय में लोग जिस तरह तनाव का जीवन जी रहे हैं, उसके कारण उनका शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। ऐसी ही एक बीमारी है उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन योगा के जरिए भी इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रभावी कुछ योगासनों के बारे में- यह एक बेहद आसान आसन है। इसका अभ्यास करने के लिए पहले आप जमीन पर बैठ जाएं।

शरीर में आयरन की कमी होने पर दिखाई देते हैं ये संकेत

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में जब शरीर में किसी एक तत्व की भी कमी हो जाए तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही जब शरीर में हर समय थकावट और सांस लेने में मुश्किल हो तो समझ लें कि शरीर में आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी की वजह से शरीर में एनीमिया की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का सही तरीके से उत्पादन नहीं हो पाता और खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी की समस्या पुरूषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। आइए जानिए शरीर में दिखने वाले कुछ संकेत जिससे आप पता लगा सकते हैं कि शरीर में आयरन की कमी हो गई है।



थकान

शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी की वजह से शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हर समय थका महसूस करता है। ऐसे में आयरन की कमी का सबसे बड़ा संकेत शरीर में होने वाली थकावट है।



काम पर फोकस न करना

आयरन की कमी होने से दिमाग पर भी असर पड़ता है जिससे व्यक्ति काम पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाता।

सांस लेने में तकलीफ

सीढ़ियां चढ़ने या ज्यादा काम करने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है लेकिन जब बैठे-बैठे भी सांस फूलने लगे तो समझ लें कि शरीर में आयरन की कमी है।

मांसपेशियों में दर्द

शरीर में आयरन की कमी की वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर कभी शरीर पर चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में काफी समय लग जाता है।

'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के दो वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन

बाल विवाह के खिलाफ अब भाषण नहीं, धरातल पर कार्रवाई जरूरी : दिया कुमारी



जयपुर (कासं)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के दो वर्ष पूर्ण होने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित बाल विवाह एवं जबरन विवाह उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को एचसीएम रीपा परिसर स्थित भगत सिंह मेहता सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष कर अपना जीवन संवारने वाली साहसी बालिकाओं और चेंज एजेंट्स को सम्मानित किया।

दिया कुमारी ने कहा कि बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान को जन-आंदोलन बनाना होगा। अब केवल भाषण नहीं, बल्कि धरातल पर कार्रवाई की जरूरत है। यह अभियान बेटियों और बेटों के सम्मान, अधिकार तथा राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से यह अभियान राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है। यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें। हर पंचायत, गांव और ढाणी को बाल विवाह मुक्त बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शादी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उम्र शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सपनों को साकार करने की है। सभी को इस अभियान का चैंपियन और ब्रांड एंबेसडर बनना होगा।

शासन सचिव पूनम ने कहा कि बाल विवाह केवल गरीबी का नहीं, बल्कि मानसिकता और सामाजिक सोच का विषय है। बेटियों को कम उम्र में गृहस्थी की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय उन्हें डॉक्टर, शिक्षक और वैज्ञानिक बनने के अवसर देने चाहिए। प्रदेश में वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है।

बाल अधिकारिता विभाग की ओर से बताया गया कि जनवरी 2026 में नई कार्ययोजना के तहत ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों और संस्था प्रधानों को भी बाल विवाह रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई है। निषेधाज्ञा लेना अनिवार्य किया गया है तथा मिशन वात्सल्य और कवच के माध्यम से पंचायत स्तर पर संरक्षण व्यवस्था मजबूत की जा रही है। बाल विवाह रोकथाम पोर्टल को शाला दर्पण से जोड़ने का प्रस्ताव भी है।

कार्यक्रम में 'बचपन बचाएंगे, बाल विवाह मिटाएंगे' संदेश के साथ जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही बाल विवाह रोकथाम पोर्टल एवं जागरूकता सामग्री का विमोचन किया गया। अभियान के थीम गीत 'बचपन को मिले उड़ान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान' का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मनोज कुमारी, हर्षिता मेघवंशी, मयंक सिंह, अंजू, अरबिया, आयशा और आरुषि बैरवा सहित बाल विवाह रोकथाम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले चेंज एजेंट्स को सम्मानित किया गया। आयशा ने छह बाल विवाह रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल विवाह रोकथाम के प्रयासों के लिए संबंधित संस्था को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

सवाई माधोपुर की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर कविता मीणा ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में एक संस्था से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी बहन और राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी सहेली का बाल विवाह रुकवाया। उनके प्रयासों से उनकी ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त बनी।

इसी पंचायत की अनंता और ज्योति जैसी बेटियां कजाकिस्तान में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कार्यक्रम में सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, जोधपुर के कुलगुरु आलोक त्रिपाठी, आयुक्त बाल अधिकारिता निकया गोहाएन, आयुक्त विशेष योग्यजन इकबाल खान, त्रिशा पारीक, अंतरा त्रिवेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, मीडियाकर्मी और बच्चे उपस्थित रहे।

न्यूज इनबॉक्स

जयपुर पुलिस कमिश्नर कल पुलिस थाना खोरा बिसल पर करेंगे जनसुनवाई

जयपुर (कासं)। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कल 28 नवम्बर (शनिवार) को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक पुलिस थाना खोरा बिसल पर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान झोटवाड़ा सर्किल के खोरा बिसल, झोटवाड़ा, करधनी, मुरलीपुरा और कालवाड़ थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की परिवेदनाओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है।

पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक एवं डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल मिलेंगे

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठा एवं सराहनीय कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक एवं डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) बिपिन पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए शान्तनु कुमार सिंह (उप महानिरीक्षक पुलिस) का चयन किया गया है। इसी प्रकार डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल के लिए पांच पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। इनमें सहायक निदेशक अभियोजन भंवर कुलदीप राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अदिति कांवत, पुलिस उप अधीक्षक निसार खान, उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं हेड कांस्टेबल नंबर 38 शाहिद अली शामिल हैं। इन्हें 14 दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा।

आज से जयपुर में साइबर सुरक्षा हैकाथॉन

जयपुर (कासं)। साइबर अपराधियों के नए-नए तरीकों पर अंकुश लगाने और पुलिस जांच को तकनीक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पुलिस और राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) की ओर से 'साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन-2026' आयोजित होगा। राजस्थान पुलिस अकादमी में 28 और 29 नवंबर को हैकाथॉन में देशभर से चयनित 37 टीमें 24 घंटे तक लगातार काम कर साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान और डिजिटल टूल्स विकसित करेंगी। हैकाथॉन का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 10 बजे महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत करेंगे। वहीं, 29 नवंबर को शाम 4 बजे हैकाथॉन का समापान समारोह होगा। इसमें मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) वी.के. सिंह ने बताया कि हैकाथॉन का उद्देश्य पुलिसिंग में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित एवं आधुनिक तंत्र विकसित करना है। इस आयोजन में स्टार्टअप और तकनीकी संस्थानों को भी अपने साइबर सुरक्षा उत्पाद एवं समाधान प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। पुलिस की इस पहल से विद्यार्थियों, तकनीकी विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ने के साथ साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान के लिए नए तकनीकी विकल्प मिलेंगे।

1930 हेल्पलाइन से लेकर मनी रिकवरी तक पर काम

एडीजी वीके सिंह ने बताया कि इसमें तकनीकी मॉडल तैयार करने के साथ-साथ पुलिस के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के समाधान भी तलाशे जाएंगे। इसमें 1930 साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई, ठगी की रकम की रिकवरी, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम तथा साइबर अपराधों से जुड़े कार्यों के ऑटोमेशन पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा साइबर अपराधों की जांच, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई और साइबर हॉटस्पॉट की पहचान कर प्रभावी प्रवर्तन के लिए तकनीकी उपाय विकसित किए जाएंगे।

— होंगे 5 तकनीकी सत्र

दो दिवसीय हैकाथॉन में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (आर4सी) की कार्यप्रणाली, साइबर अपराधों से निपटने के प्रभावी उपाय और आधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों पर विशेषज्ञ सत्र भी होंगे। पहले दिन पांच सत्र होंगे। इनमें 1. 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं साइबर अपराधों से बचाव और त्वरित कार्रवाई, 2. महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराध, 3. साइबर ठगी की राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया एवं शिकायत निवारण मॉड्यूल, 4. साइबर अपराधों से संबंधित प्रक्रियाओं का स्वचालन (प्रोसेस ऑटोमेशन) और 5. साइबर अपराध हॉटस्पॉट पर प्रभावी प्रवर्तन एवं कार्रवाई प्रमुख हैं।

— 5 तकनीकी चुनौतियों पर होंगे नवाचार

प्रतियोगिता में पांच प्रमुख समस्या क्षेत्रों पर टेक्निकल टीमें रिसर्च करेंगी। इनमें 1.फर्जी वेबसाइट, फिशिंग लिंक और संदिग्ध ऐप के जरिए होने वाली ठगी की पहचान करना 2. टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर अवैध गतिविधियों की निगरानी, 3. एआई आधारित जांच सहायक के साथ सीडीआर एवं

प्रवासी राजस्थानी दिवस : 8 से 10 दिसंबर तक भव्य आयोजन

मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की, सभी कार्य समय पर पूरे करने के दिए निर्देश



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इस वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन तीन दिवसीय होगा। इस आयोजन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस आयोजन में 'विकास भी, विरासत भी' की झलक दिखाई देनी चाहिए। राजस्थान की भव्य विरासत और विकास को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित किया जाए। प्रवासियों को अपनापन महसूस हो और वे अच्छी यादों के साथ वापस लौटें। उन्होंने मुख्य आयोजन और विशेष सत्रों की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ ही राजस्थान फाउंडेशन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, माइंस और सूचना एवं जनसंपर्क सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि 10 दिसंबर को छह विशेष सत्र होंगे। इनमें पर्यटन, शहरी विकास, उद्योग, ऊर्जा, माइनिंग और प्रवासी राजस्थानी संवाद शामिल हैं। इन सत्रों में विकसित राजस्थान-2027 की थीम के अनुरूप भविष्य की तस्वीर नजर आनी चाहिए। आयोजन के दौरान विशिष्ट अतिथियों के वीवीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा, प्रोटोकॉल, आवास, परिवहन और अतिथि सत्कार की विशेष व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जयपुर शहर के सौंदर्यीकरण के तहत सफाई अभियान, सड़कों की मरम्मत, रोशनी की व्यवस्था और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के सुधार का कार्य भी समय पर पूरा कर लिया जाए। बैठक में बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश-विदेश में बसे प्रवासियों और निवेशकों में उत्साह है। अब तक 7,500 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है।

दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 8 दिसंबर को झुंझुनूं के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट और 9 दिसंबर को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रवासी सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रवासियों को आमंत्रित करने के लिए कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में 'प्रवासी राजस्थानी मीट' का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने 16 अक्टूबर को जयपुर में प्रवासियों के साथ संवाद भी किया था, जिसमें देश-विदेश में बसे प्रवासी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।



राज्यपाल से भारतीय पुलिस सेवा के नव प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शुक्रवार को लोक भवन में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2024 और 2025 बैच के नव प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल बागडे ने इस दौरान नव प्रशिक्षु अधिकारियों को 'राष्ट्र प्रथम' की सोच से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा के साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी अधिकारी प्रतिबद्ध होकर समर्पित भाव से कार्य करें।

बागडे ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आम जन का विश्वास अर्जित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की साख इस बात पर है कि समाज में अपराध की प्रवृत्ति कम से कम रहे। पुलिस से अपराधियों में भय व्याप्त रहेगा तभी उनका इकबाल बना रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अवसर है। अधिकारियों को कानून के प्रति सम्मान रखते हुए निष्पक्षता से काम करना चाहिए।

कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में पुलिस की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों और बदलती आपराधिक चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने नव प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में अनुशासन, संवेदनशीलता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय से ही सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज की स्थापना संभव है।

राज्यपाल ने विश्वास जताया कि सभी अधिकारी अपनी सेवाओं के माध्यम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे।

शहर की स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर सुनील कोठारी ने ली समीक्षा बैठक

सफाई सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश



जयपुर (कासं)। नगर निगम जयपुर द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, कचरा प्रबंधन को प्रभावी करने तथा व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग के उद्देश्य से शुक्रवार को महापौर सुनील कोठारी की अध्यक्षता में नगर निगम मुख्यालय स्थित ई.सी. मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपमहापौर श्रीमती सरोज कंवर, अतिरिक्त आयुक्त नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त (स्वास्थ्य) ओम थानवी, समस्त जोन उपायुक्त, उपायुक्त पशु प्रबंधन, अधिशाषी अभियंता गैराज, अधिशाषी अभियंता प्रोजेक्ट एवं समस्त जोन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में महापौर सुनील कोठारी ने सभी अधिकारियों को सख्त लहजे से कहा कि शहर की सफाई प्राथमिकता है यदि उसमें कोई भी लापरवाही होती है तो सख्त कार्रवाई की जायेगी। महापौर ने सभी जोन उपायुक्तों को निरन्तर फील्ड मॉनिटरिंग करने के निर्देष दिये ताकि शहर में ओपन कचरा डिपो ना हो। इसके साथ ही प्रोजेक्ट शाखा के अधिकारियों को कहा कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के तहत आने वाले वाहनों की निगरानी सुनिष्चित करें। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि सभी दुकानदारों को दो डस्टबिन (गीले व सूखे कचरे) नीला व हरा डस्टबिन रखना अनिवार्य है। पहले समझाईष की जायेगी उसके बाद सख्ती के साथ 2 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ सफाई एवं कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए जोन स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया जाये। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था की स्थिति, नगर निगम क्षेत्र में ओपन कचरा डिपो की स्थिति, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, जनगणना की अद्यतन तैयारियां, वार्ड ओआईसी द्वारा किए जा रहे निरीक्षण की स्थिति, कैरिंग चार्ज एवं जुर्माने की स्थिति, दुकानों पर दो डस्टबिन की व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट, जोन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान देशभर में अव्वल

प्रधानमंत्री के 'वंचितों को वरीयता' के विजन को साकार कर रहा राजस्थान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन मोड पर चल रहा अभियान

जयपुर (कसयं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'वंचितों को वरीयता' के विजन के साथ प्रारम्भ किए गए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का प्रभावी क्रियान्वयन कर राजस्थान ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन मोड पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, राजकीय सेवा की समयबद्ध उपलब्धता, शिकायतों के प्रभावी निवारण और जनजातीय समुदाय के अधिकारों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में यह विशेष उपलब्धि हासिल की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान के 37 जिलों के 208 ब्लॉक्स के 6 हजार 19 गांवों में आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के निर्माण, उन्नयन एवं सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक विभिन्न विकास कार्यों के लिए 335 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी किए जाने के साथ 277 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इनके लिए भारत सरकार से 177 करोड़ रुपये से अधिक की मदर स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। देशभर के जनजातीय गांवों के परिदृश्य में बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहे इस अभियान में प्रदेश के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां एवं सिरोही जिलों में कुल 6 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन विपणन केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन को बेहतर बनाते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा, ताकि जनजातीय समुदायों की आय एवं आजीविका के अवसरों में वृद्धि हो सके। अभियान के अंतर्गत जनजातीय समुदायों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और समस्या-समाधान की सोच विकसित करने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी अभियान की पहल की गई है। इसके प्रथम चरण में राजस्थान में 26 जिलों के 5 हजार 978 गांवों को शामिल करते हुए 162 जिला मास्टर ट्रेनर्स, 1 हजार 82 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स एवं 1 लाख 16 हजार 670 ग्राम स्तरीय आदि कर्मयोगियों एवं आदि सहयोगियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक जनजातीय नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए देशभर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की एक ऐतिहासिक पहल की है।

जनजाति कल्याण को समर्पित इस अभियान का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के अंतर को दूर करते हुए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों के साथ लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है। मार्च 2029 तक क्रियान्वित किए जाने वाले इस अभियान में 17 मंत्रालयों की 25 गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 2 हजार 911 ब्लॉकों के 63 हजार 843 जनजातीय गांवों को लक्षित किया गया है।

कचरा पॉइंट का कायाकल्प, रंगोली-वॉल पेंटिंग से निखरा स्थल

जयपुर (कासं)। नगर निगम महापौर सुनील कोठारी एवं आयुक्त ओम कसेरा के निर्देशन में नगर निगम जयपुर द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से निरंतर विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उपायुक्त, सिविल लाइंस जोन द्वारा क्लीन स्वीप ड्राइव के अंतर्गत सिविल लाइंस जोन के सोडाला, अजमेर रोड स्थित हाईवे के किनारे स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए कचरा पॉइंट का कायाकल्प किया गया। अभियान के तहत उक्त स्थान से कचरे को हटाकर विशेष साफ-सफाई करवाई गई तथा आकर्षक वॉल पेंटिंग एवं सुंदर रंगोली बनाकर स्थल का सौंदर्यीकरण किया गया। इस पहल से पूर्व में गंदगी से प्रभावित रहने वाला स्थान अब स्वच्छ, सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप में नजर आने लगा है। महापौर सुनील कोठारी एवं आयुक्त ओम कसेरा के निर्देशन में नगर निगम द्वारा स्वच्छता के साथ-साथ शहर के सार्वजनिक स्थलों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यालय जिला परिषद भीलवाड़ा

Bid Invitation Notice

Bids for Civil work for Establishment of DMFT Office at Zila Parishad Campus (Estimated Bid Value – 16,34,000) are invited from interested bidders upto 04.12.2026 till : 05:00 PM . Others particulars of the bids may be visited on the portal **(http://sppp.rajasthan.gov.in and https://eproc.rajasthan.gov.in)** of the state.

NIB : ZBL2627A1067, UBN : ZBL2627WSOB02051

Raj.Samwad/C/26/13733 — **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

राज्य विशेष शाखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक व-15 (16) पुविशा/भण्डार / स्टेशनरी/2026-27/604 — दिनांक -25-11.2026

दर संविदा हेतु बोली आमंत्रण सूचना

विभिन्न वस्तुओं के प्रदाय (Supply) करने हेतु 01 वर्ष के लिए दरें अनुमोदित करने हेतु मोहरबन्द बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 27.11. 2026 को प्रातः 11.00 बजे विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड की जाकर निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिनांक 04.12.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक भौतिक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त बोलियां दिनांक 04.12.2026 को दोपहर 04.00 बजे खोली जानी प्रस्तावित है। बोलीदाता जिन आईटम्स के लिए लिए बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसके लिए पुलिस विभाग की वैबसाईट से विभागीय बोली प्रपत्र यथा परिशिष्ट अ. ब. स. द को डाउनलोड कर सकेगा तथा विभागीय बोली शर्तों के अनुसार वांछित दस्तावेज के साथ पूर्ति करके बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके बोली प्रस्तुत की जावेगी। बोली की मुख्य शर्तें, विवरण किसी भी कार्य दिवस को निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6 (5) वित्त/सा.वि.ले. नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी चालान से ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है।

क्र. स.	वस्तु का नाम	अनुमानित कीमत	निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति (रू. में)
1.	कार्यालय उपयोग संबंधी विभिन्न स्टेशनरी आईटम एवं विविध सामान	6,26,505/-	200/-	12,530/-

UBN IS CIR2627GSRC00010

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
पुलिस अधीक्षक, आसूचना
राजस्थान, जयपुर।

DIPR/C/18674/2026

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, **Email:-** lokjeewanjpr@gmail.com **भीलवाड़ा कार्यालयः** 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। **फोनः** 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, **मो.** 8306792625